ए-45011/03/2024-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को जनवरी, 2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सु. सामंत

(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309- 5244

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के पीएस, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आर्थिक कार्य) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, डीईए।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, एएस एवं एफए (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एवं सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, एएस (ओएमआई/क्रिप्टो संपत्ति)
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागों के प्रमुख।

जेएस (आईपीपी), जेएस (आईएसडी) /जेएस (अन्वे) /जेएस (बजट) जेएस (एफएम) /सभी सलाहकार/सीएएए

17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फ़ाइल – 2024.

ए-45011/03/2024-समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषय: जनवरी माह, 2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

वृहद आर्थिक सिंहावलोकन:

5 जनवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष) के दौरान भारत की 7.3 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी वृद्धि की प्रत्याशा की पुष्टि की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी विश्व आर्थिक आउटलुक के जनवरी अपडेट में अपने अक्टूबर 2023 के पूर्वानुमान को 6.3 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत तक संशोधित करके वित्त वर्ष 24 में भारत के अपेक्षित मजबूत विकास प्रदर्शन का समर्थन किया। निजी उपभोग और निवेश ने मांग पक्ष से वृद्धि में सहायता प्रदान करना जारी रखा है; जबकि आशावादी विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र इसे आपूर्ति पक्ष से सुदृढ़ करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में निर्माण क्षेत्र के 10.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसे रियल एस्टेट की बढ़ती घरेलू मांग से संबल प्राप्त हुआ है।

पूंजीगत व्यय पर सरकार का सुदृढ़ फोकस, जिसका उद्देश्य अवसंरचना के अंतराल को पाटना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है, ने भी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत गुणक प्रभाव प्रदान करना जारी रखा है। पूंजीगत व्यय के लिए कुल व्यय के पुनर्संतुलन के परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व और पूंजीगत व्यय का अनुपात वित्त वर्ष 2021 में 8.6 से अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान वित्त वर्ष 24 में 4.1 हो गया। पूंजीगत व्यय पर राज्यों का बल भी जारी रहा और अप्रैल-नवंबर के दौरान पूंजीगत व्यय में 42.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दिसंबर 2023 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत थी और अधिसूचित टोलरैंस बैंड के भीतर रही। यह खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद था, जो दिसंबर में 9.5 प्रतिशत थी, और पिछले महीने में 8.7 प्रतिशत से अधिक थी। दालों, प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों ने खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर, मुख्य मुद्रास्फीति में इसके प्रमुख घटक में लगातार 7वें महीने गिरावट देखी गई है, जो दिसंबर में 3.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह पिछले 49 महीनों में सबसे कम कोर मुद्रास्फीति है।

निर्यात वृद्धि में कमी के बावजूद, भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान बढ़कर 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 212 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण व्यापारिक वस्तुओं के आयात में अधिक गिरावट आई जिससे व्यापार संतुलन बेहतर हुआ। भारत के व्यापारिक निर्यात में अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 5.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण भारत के व्यापारिक भागीदारों की अर्थव्यवस्थाओं में हुई कम वृद्धि है। फिर भी, इस अवधि में भारत के इलैक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 22.2

प्रतिशत की वृद्धि हुई - जो स्मार्टफोन शिपमेंट में वृद्धि के कारण है। इंडिया सेल्युलर एंड इलैक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान मोबाइल फोन का निर्यात कुल मिलाकर 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुल निर्यात का लगभग 52 प्रतिशत है।

लंबे समय से चलता आ रहा अत्यंत गंभीर रेड सी क्राइसिस दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक पूर्वानुमानों के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसका बाहरी संतुलन, मुद्रास्फीति और विकास पर असर पड़ता है। रेड सी क्राइसिस के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीका तथा मिडल ईस्ट के कुछ हिस्सों में शिपमेंट के लिए शिपिंग और बीमा लागत में वृद्धि हुई है। लाल सागर के रास्ते से बचने के लिए, शिपमेंट को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए लंबे मार्ग से ले जाया जा रहा है, जिससे शिपिंग कंटेनरों का टर्नअराउंड समय लगभग 14 दिनों तक बढ़ गया है।

2. महत्वपूर्ण विकास :

(i) भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि में माननीय वित्त मंत्री ने 12 जनवरी, 2024 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार श्री इमैनुएल बोने से मुलाकात की।

(ii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं/उनमें भाग लिया गया :

क. **भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) वार्ता** का 18वां दौर दिनांक 8-10 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

ख. **भारत-यूएई बीआईटी वार्ता का 19वां दौर दिनांक 18 जनवरी, 2024 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया था।**

ग. ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत, भारत और यूके की सह-अध्यक्षता में पहली जी20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक और फ्रांस और दक्षिण कोरिया की सह-अध्यक्षता में **पहली जी20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की** वर्चुअल **बैठक क्रमशः** 17-18 जनवरी, 2024 और 24-25 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी। ये बैठकें 2024 के लिए एफडब्ल्यूजी और आईएफए डब्ल्यूजी के तहत कार्य योजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गईं। इन बैठकों के परिणाम फरवरी 2024 में होने वाली जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों तथा जी20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की बैठकों के दौरान चर्चा का आधार बनेंगे।

घ. दिनांक 18-19 जनवरी, 2024 2024 को नई दिल्ली में **"पीपीपी संरचना टूलकिट-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन"** पर कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ङ. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत विभिन्न देशों को दी जाने वाली क्रेडिट लाइनों के लिए द्विवार्षिक समीक्षा बैठक 18-19 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

च. 9वीं मंत्रिस्तरीय भारत-यूएसए आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने 22 जनवरी, 2024 को तीसरी तिमाही समीक्षा की बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित की।

छ. भारत-यूएई बीआईटी तकनीकी चर्चा दिनांक **24 जनवरी, 2024** को डीवीसी के माध्यम से आयोजित की गई।

ज. भारत-यूके बीआईटी पर अनुवर्ती बैठक (सचिव, डीईए और यूनाइटेड किंगडम के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच) 24 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

झ. आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी की मिड-ईयर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक **24 जनवरी 2024** को आयोजित की गई, जिसमें वित्त वर्ष **2024** के लिए कार्य योजना के मसौदे पर चर्चा की गई।

ञ. एनडीबी निदेशक मंडल ने दिनांक 30 जनवरी, 2024 को एक विशेष बीओडी बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

ट. सचिव, आर्थिक कार्य ने **26** जनवरी, **2024** को फ्रांस के सेक्रेट्री ऑफ ट्रेजरी एंड फाइनेंस ट्रेजरी श्री बर्ट्रेंड ड्यूमॉन्ट से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

ठ. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर 145वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 30 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी।

ड. एआईआईबी निदेशक मंडल की वर्चुअल बैठक **31** जनवरी, **2024** को हुई।

ढ. भारत-कोरिया सीईपीए (निवेश सुरक्षा मुद्दों पर) पर 10वें दौर की बातचीत 30-31 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई।

(iii) आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के दूसरे चरण के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा **25** मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त में से **12.025** मिलियन अमेरिकी डॉलर **(100** करोड़ रुपये) की पहली किस्त का आईएमएफ को भुगतान किया गया।

(iv) न्यू डेवलपमेंट बैंक **(एनडीबी)** के साथ निम्नलिखित ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

i. शहरी बाढ़ को कम करने के लिए लाम्फेलपैट जल निकाय के कायाकल्प, इम्फाल शहर के लिए स्थायी जल स्रोत प्रदान करने और 70.27 मिलियन अमरीकी डालर के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने हेतु।

ii. इंफाल सिटी चरण II के लिए एकीकृत सीवरेज प्रणाली हेतु 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

iii. गुजरात ग्रामीण सड़क (एमएमजीएसवाई) परियोजना हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

(v) **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई:**

क) "ऋण लेने संबंधी व्यवस्था में क्रेडिट व्यवस्था को बंद करना" के संबंध में आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड दस्तावेज़। डीईए ने भारतीय ईडी के बयान के माध्यम से बोर्ड के प्रस्ताव का समर्थन किया।

ख) 11 जनवरी, 2024 को पाकिस्तान के संबंध में कार्यकारी बोर्ड की बैठक - स्टैंड-बाय व्यवस्था के तहत पहली समीक्षा, परफोर्मेंस मानदंड का पालन न करने की छूट, परफोर्मेंस मानदंड में संशोधन और पहुंच की पुनर्रचना के लिए अनुरोध। पहले की भांति, पाकिस्तान के एसबीए के तहत पहली समीक्षा पर मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया है। ईडी (भारत), आईएमएफ से अनुरोध किया गया था कि वह आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड को सूचित करे कि वह "जांच और संतुलन स्थापित करें और पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ फंडिंग के उपयोग की विशेष निगरानी सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त निधि को रक्षा व्यय और अन्य देशों पर बकाया विदेशी ऋण की अदायगी के लिए डायवर्ट न किया जाए।"

(vi) अवसंरचना क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा और अधिक निवेश को बढ़ावा देने तथा व्यापार करने में सुगमता हेतु, **अवसंरचना ऋण कोष (आईडीएफ) में निवेश के लिए केस-टू-केस अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।** बीमाकर्ताओं को आईडीएफ-एनबीएफसी में निवेश करने की अनुमति है जिसे कुछ शर्तों के अध्यधीन अवसंरचना में निवेश माना जाएगा।

(vii) **माह के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की गईं:**

क. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) - दिनांक 24 जनवरी, 2024 को अंतरराष्ट्रीय विनिमय योजना में भारत में शामिल कंपनियों की इक्विटी शेयरों की डायरेक्ट लिस्टिंग से संबंधित संशोधन नियम अधिसूचित किए गए।

ख. 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 75/- रु. मूल्य का स्मारक सिक्का।

ग. वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 20/- रु. मूल्य का स्मारक सिक्का।

घ. स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100/- रु. मूल्य का स्मारक सिक्का।

ङ. शाहजहाँपुर के श्री राम चंद्र जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125/- रु. मूल्य का स्मारक सिक्का।

च. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर 150/- रु. मूल्य का स्मारक सिक्का।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी दिशानिर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन के लिए लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या : 03

विभाग में अनुमोदन के लिए लंबित : 08

7. जनवरी, 2024 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित वीजीएफ परियोजनाओं की संख्या: शून्य

8. जनवरी, 2024 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित पीपीपीएसी परियोजनाओं की संख्या: शून्य।

9. जनवरी, 2024 के दौरान भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत अनुशंसित एलओसी: शून्य

10. जनवरी, 2024 के दौरान डीईए की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या: नौ प्रस्ताव।